भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4322
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

बाल भिक्षावृत्ति

4322. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में गरीब बच्चों को भिक्षा मांगने और अपराध करने के लिए मजबूर करने की घटनाएं बढ़ी हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त प्रथा में शामिल दम्पतियों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या व्यवस्था है;
- (घ) क्या बच्चों को अपराध करने के लिए मजबूर करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए कोई व्यवस्था मौजूद है; और
- (ङ) यदि हां, तो आज तक इस संबंध में की गई-कार्रवाईयों की संख्या क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख) : गरीब बच्चों को भीख मांगने और अपराध करने के लिए मजबूर करने की घटनाओं का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ.) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय "स्माइल - आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता" केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित करता है, जिसमें भीख मांगने वाले बच्चों सहित भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए उप-योजना शामिल है। इस उप-योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण में 31 चिन्हित शहरों/कस्बों में सर्वेक्षण/पहचान कार्य शामिल है। अब तक 6-14 वर्ष के औसत आयु वर्ग के 352 बच्चों की पहचान भीख मांगने वाले के रूप में की गई है। सभी 352 बच्चों का पुनर्वास किया जा चुका है (169 को उनके माता-पिता के पास भेज दिया गया, 79 को

आंगनवाड़ी में भेज दिया गया, 33 को बाल कल्याण समिति में भेज दिया गया और 71 को स्कूलों में नामांकित कर दिया गया। इस योजना के तहत भोजन, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, पुनर्वास, बुनियादी दस्तावेजीकरण, कौशल विकास, भीख मांगने वाले व्यक्तियों के बच्चों/बच्चों को शिक्षा सहित इकोनॉमिक लिंकेज जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) संचालित करता है, जो बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है। यह अधिनियम देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) की देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार और समाज में फिर से जोड़ कर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके उनकी सुरक्षा का प्रावधान करता है। यह बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए देखरेख एवं संरक्षण के मानकों को परिभाषित करता है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) (ii) में प्रावधान है कि कोई भी बच्चा जो तत्समय लागू श्रम कानूनों के उल्लंघन में कार्य करते हुए पाया जाता है या भीख मांगते हुए पाया जाता है या बेघर है, उसे 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे' के रूप में शामिल किया गया है।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 27-30 बाल कल्याण समितियों को बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनके सीएनसीपी श्रेणी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देती है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की प्राथमिक जिम्मेदारी और निष्पादन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन वात्सल्य योजना में सीएनसीपी और सीसीएल श्रेणी के बच्चों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिनमें संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख सेवाएं दोनों शामिल हैं। इस योजना में बाल भिखारियों सहित बच्चों को उनके पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखरेख संस्थाएं अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि तक पहुंच में सहायता करती हैं। इस गैर-संस्थागत देखरेख के अंतर्गत सहायता देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रायोजन, पालन-पोषण और पश्चात देखरेख के माध्यम से प्रदान की जाती है।

मंत्रालय क्षेत्रीय स्तर पर मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ समय-समय पर बैठकें/प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ आयोजित करता है। राज्य और जिला स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ योजना की दिन-प्रतिदिन निगरानी करती हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल भिक्षावृत्ति/बाल श्रम/बाल दुर्व्यवहार पर शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित जिलों में "सड़क पर रहने वाले बच्चों (सीआईएसएस) 2.0" पर मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की है।